(ग) यदि हां, तो भारत में बने सोडा ऐश की लागत इतनी अधिक होने के क्या कारण हैं और इसकी निर्माण लागत तथा विक्रय मूल्य कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता)** : (क) और (ख). सोडा ऐश की दूसरे देशों में उत्पादन लागत तुरंत उपलब्ध नहीं है । जापान की उत्पादन लागत की विश्वसनीय सूचना के अभाव में अपनी उत्पादन लागत से उसकी तुलना करना संभव नहीं है । फिर भी साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि सोडा ऐश की उत्पादन लागत भारत में, और दूसरे महत्वपूर्ण उत्पादनशील देशों से अधिक है ।

(ग) भारत में अधिक लागत होने के मुख्य कारण हैं:—कारखानों का छोटा आकार, कच्चे माल, संयन्त्र और मशीनरी तथा विद्युत शक्ति की अधिक लागत आदि ।

उत्पादन लागत को कम करने के जो उपाय विचाराधीन हैं उनमें से कुछ हैं : वर्तमान कारखानों का आर्थिक आकार तक विस्तार करना तथा मोडीफाइड सोलवे प्रक्रिया नामक आधुनिकतम प्रक्रिया का अपनाना ।

**समाज से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग**

*1664. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज से जातिपाति, प्रान्तीयता और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने लिए आर्य समाज और ऐसे अन्य सामाजिक संगठनों का, जो लगभग पिछले 100 वर्षों से इन बुराइयों को दूर करने में संग्लन है, सहयोग मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी सेवाओं का किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है ?

**समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह)** : (क) से (ग). सरकार की नीति रही है कि धर्म निरपेक्ष स्वैच्छिक संस्थाओं के सामजिक कार्य को बढ़ावा दे । समाज सुधार कार्य की इच्छुक धर्म निरपेक्ष और भी गैर-राजनीतिक संस्थाओं के विशिष्ट प्रस्तावों पर सरकार, विभागीय बजट की सीमाओं के भीतर, विचार करने को तत्पर होगी ।

**भारत सहायता सार्थसंघ की बैठक**

*1665. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से कहा गया है कि वह अपने परिवार नियोजन तथा कृषि कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्यौरा प्रस्तुत करे ताकि मई, 1968 के दूसरे पखवाड़े में होने वाली भारत सहायता सार्थसंघ की बैठक में उस पर विचार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस ब्यौरे को प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ?

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत की आर्थिक सहायता सम्बन्धी आवश्यकता पर विचार करते समय भारत सहायता संघ भारतीय आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करता है और आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि-उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, परिवार-नियोजन आदि के क्षेत्रों में हुए विकास को ध्यान में रखता है । इस प्रयोजन के लिए भारत सहायता संघ को उपयुक्त सूचना दी जाती है ।

**Gold Reserve System**

*1666 SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India plan to go off the gold reserve system;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, how far it has helped in maintaining monetary stability in the country since the First Plan period?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The Reserve Bank of India Act requires that a certain minimum amount of gold be held as asset of the Issue Department. There is no proposal at present to make a change in this system.

(b) Does not arise.

(c) Monetary stability does not depend on the composition and size of the legal reserves, but on the overall balance between supply and demand in the economy.

**Sindri Unit of Fertiliser Corporation**

*1667. SHRI K. M. ABRAHAM :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI P. GOPALAN :
SHRI UMANATH :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) when the Second Pay Commission's recommendations were implemented in Sindri Unit of the Fertilizar Corporation of India;

(b) whether it is a fact that chargemen have not been paid according to the recommendations of the Second Pay Commission since the 1st April, 1964;

(c) whether it is also a fact that the Labour Department of the Government of Bihar informed the General Manager, Sindri Unit of the Fertilizer Corporation of India that the Chargemen are entitled to the benefits of the Second Pay Commission's recommendations since implemented in Sindri;

(d) if so, the reasons for not paying the arrears to the Chargemen ; and

(e) the steps taken by Government to pay the arrears ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) The recommendations of the Second Pay Commission are not automatically applicable to the employees of the Sindri Unit. However, on the analogy of these recommendations the pay scales of non-workmen of the Sindri Unit were revised with effect from 1st April 1964.

(b) The Chargemen being in the scale of Rs. 320-15-470 were considered to be workmen governed by the award of the Bihar Industrial Tribunal and were not brought within the scope of the revision of the pay scales referred to at (a) above. However, on their special request, they were subsequently allowed to opt out of the Bihar Industrial Tribunal Award so that they could get the benefit of the revision on the analogy of the Second Pay Commission's recommendations. This took effect from 1.3.1967.

(c) Yes, Sir. It was after the receipt of Bihar Government's advice that the Chargemen were allowed to opt out of Bihar Industrial Tribunal Award and their scales revised on the analogy of the Second Pay Commission's recommendations with effect from 1.3.1967.

(d) and (e). As the scales were revised with effect from 1st March 1967, the question of payment of arrears does not arise.

**L. I. C. Business**

*1668. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a persistent decline in recent years in the ratio of the Life Insurance Corporation's new business actually completed to the business received ;

(b) whether it is also a fact that the growth rate of new business comleted in 1967-68 was much lower as compared to 1965-66 ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps taken to check this trend ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) The completion-ratio declined from 95.4 in 1965-66 to 94.4 in 1966-67 and to 93.6 in 1967-68. This fall cannot be considered to be significant.